RAJYA SABHA

Wednesday, the 3rd August, 2005/12 Sravana, 1927 (Saka)

The House met at eleven of the clock

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता

*141. **श्री मोती लाल वोरा**:†

श्री जनार्दन द्विवेदी:

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थाईलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि थाईलैंड से आयातित 82 वस्तुओं पर आयात शुल्क बहुत अधिक कम देने से थाईलैंड का सामान भारतीय सामान से अधिक सस्ता है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय उद्योग को बंद होने से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) भारत ने थाईलैंड के साथ अब तक किसी मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, भारत और थाईलैंड ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफ टी ए) की स्थापना हेतु 9 अक्तूबर, 2003 को केवल एक कार्यढांचा करार पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य घटकों में, वस्तुओं, सेवाओं एवं निवेश में एफ टी ए तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कार्यढांचा करार में एक शीघ्र फलदायी योजना (ई एच एस) का भी प्रावधान है, जिसके तहत फास्ट ट्रैक आधार पर ट्रैफिक की समाप्ति हेतु 82 साझा मदों पर सहमति हुई है।

---

† सभा में यह प्रश्न श्री मोती लाल वोरा द्वारा पूछा गया।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) से (घ) ई एच एस में शामिल किए गए उत्पादों के संबंध में टैरिफ में निम्नलिखित कमी की जाएगी:-

अवधि	दिनांक 1 जनवरी, 2004 की स्थिति के अनुसार लागू एम एफ एन टैरिफ दरों पर टैरिफ कमी
1.9.2004-31.8.2005	50%
1.9.2005-31.8.2006	75%
1.9.2006	100%

शीघ्र फलदायी स्कीम के अंतर्गत वस्तुओं की सूची को प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों तथा घरेलू पणधारकों के साथ परामर्श करने के पश्चात अंतिम रुप दिया गया है। टैरिफ अधिमान केवल उन्हीं उत्पादों के लिए उपलब्ध होगे जिन्हें उद्‌गम संबंधी नियमों,जो मुक्त व्यापार करार के अभिन्न अंग हैं,के तहत यथा निर्धारित "उद्‌गम का दर्जा" प्राप्त है। करार में व्यापार रक्षा उपायों का भी प्रावधान है जिन्हें कोई आयातक देश लागू कर सकता है। आयातों में वृद्धि होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की स्थिति में किसी देश को पाटनरोधी उपायों तथा रक्षोपायों जैसे उपाय लागू करने की अनुमति है।

FTA with Thailand

†*141. SHRI MOTILAL VORA:††
SHRI JANARDAN DWIVEDI:

Will the Minister of COMMERCE & INDUSTRY be pleased to state:

(a) the terms of Free Trade Agreement with Thailand;

(b) whether it is also a fact that due to heavy reduction in the import duty on 82 items imported from Thailand, the goods of Thailand are cheaper than that of India;

(c) if so, the steps being taken by Government to save Indian industry from closure; and

†Original notice of the question was received in Hindi.
††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Moti Lal Vora.

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH): (a) India has not yet signed any Free Trade Agreement with Thailand. However, on 9th October 2003 India and Thailand have signed only a Framework Agreement for establishing a Free Trade Area (FTA). The key elements cover FTA in Goods, Services and Investment, and other areas of Economic Cooperation. The Framework Agreement also provides for an Early Harvest Scheme (EHS) under which 82 common items have been agreed for elimination of tariffs on a fast track basis.

(b) to (d): A statement is laid on the table of the House.

Statement

(b) to (d) The products covered under EHS are subject to the following tariff reduction:

Period	Tariff reduction on applied MFN tariff rates as on 1st January 2004
1.9.2004—31.8.2005	50%
1.9.2005—31.8.2006	75%
1.9.2006	100%

The list of items under the Early Harvest Scheme has been finalised after consultations with the administrative Ministries/Departments and the domestic stakeholders. The tariff preferences would be available only for those products which enjoy the 'originating status' as prescribed under the Rules of Origin which are-integral part of the Free Trade Agreement. The Agreement also provides for trade defence measures which an importing country can take recourse to. In case of a surge in imports and injury to the domestic industry, a country is allowed to take measures such as anti-dumping and safeguards.

श्री मोती लाल वोरा:माननीय सभापति जी,माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि भारत और थाईलैंड के बीच में अभी मुक्त व्यापार करार नहीं हुआ है,लेकिन कार्यढांचा करार किया गया है। माननीय सभापति महोदय,उस करार के अन्तर्गत 82 वस्तुएं जो थाईलैंड से भारतवर्ष में आयेंगी जिसके कारण भारतवर्ष में उत्पादन करने वाले जो छोटे-छोटे उद्योग हैं,उद्योगपति हैं,वे उनके सामने टिक पायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इस प्रकार

का कर ढांचा करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इस बात की जानकारी ली थी कि इलैक्ट्रोनिक उद्योग में अनेक प्रकार की जो वस्तुएं निर्मित होती हैं,उन्हें अपना निर्माण बंद करना पड़ेगा या उन्हें थाईलैंड के माल को खरीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि जिस कार्यढांचा करार पर आपने हस्ताक्षर किए, क्या उसके बाद थाईलैंड से भारतवर्ष में से वस्तुएं आना शुरु हो गई हैं?

श्री कमल नाथ:सर, जैसा कि जवाब में कहा है कि 9 अक्टूबर, 2003 में यह एग्रीमेंट साइन हुआ था और इसके तीन-चार अंग हैं। सबसे पहला इसका अंग Early Harvest Scheme था। इस Early Harvest Scheme में काफी ऐसे प्रोडक्ट चुने गये,जिनको ड्यूटी रिडक्शन दिया जायेगा। इनको पहले साल में 50 परसेंट ड्यूटी रिडक्शन दिया जायेगा,तत्पश्चात 75 परसेंट और 1 सितम्बर, 2006 से ये 82 आइटम्स भारत के और थाईलैंड के इनको सौ प्रतिशत ड्यूटी एक्जम्पशन दिया जायेगा। यह Early Harvest Scheme उसका अंग था,उस एग्रीमेंट का था,जिसकी शुरुआत नवम्बर,2001 में,जब प्रधान मंत्री जी थाईलैंड गये थे,दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच में यह एग्रीमेंट साइन हुआ था,एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप शुरु हुआ था। वर्ष 2003 में उस समय के वाणिज्य मंत्री और थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किये थे। उसके बाद ये 82 आइटम्स जो हैं, सब अपने देश की संस्थाओं से,संगठन से चर्चा करके,जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन चीजों का हमारे यहां उत्पादन होता है,उसमें जहां हमारी क्षमता है,इस क्षमता को देखते हुए,ये 82 आईटम्स तय किये गये थे। ये 82 आइटम्स लगभग 7 प्रतिशत भारत और थाईलैंड के व्यापार को कवर करते हैं।

अब जो इसका दूसरा अंग है,उस पर चर्चा हो रही है, ताकि यह समझौता, जिस पर हस्ताक्षर किये गये अगले दो-तीन साल में इसका कोई निचोड़ निकल सके और इसका समापन हो सके।

श्री मोती लाल वोरा:माननीय सभापति महोदय,माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये जो 82 आइटम्स हैं,इनके लिए आपने जो कर में छूट दी है, जैसा कि आपने कहा कि 1.9.2004 से 31.8.2005 तक 50 प्रतिशत, 1.9.2005 से 31.8.2006 तक 75 प्रतिशत और 1.9.2006 से 100 प्रतिशत-थाईलैंड का जो माल यहां आएगा,यह छूट आपने उनको दी है। तो क्या भारतवर्ष में जो उद्योगपति हैं,उनको यह छूट नहीं है? थाईलैंड में जहां ब्याज की दरें 4 और 5 प्रतिशत हैं,भारत के ये कम से कम 13 प्रतिशत हैं। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए,क्या भारत के उद्योगपति या छोटे उद्योगपति, थाईलैंड से आने वाले माल का मुकाबला करेंगे या उनके अपने उद्योग बंद हो जाएंगे? क्या माननीय मंत्री जी ने इस पर विचार किया है?

श्री कमल नाथ:सर,माननीय सदस्य की यह बात सही है,क्योंकि जो पहला अनुभव था,भारत का इस प्रकार का पहला समझौता श्रीलंका से हुआ था और फिर दो साल बाद, थाईलैंड से

हुआ। आज अगर हमारी इच्छा है कि हम एशिया में,खासकर हमारे जो पड़ोसी देश हैं- सार्क हो,BIMSTEC हो- उनसे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहें,तो हमें कुछ देना भी पड़ता है और हमें कुछ मिलता भी है। हमारे जो उद्योग हैं,हमारे उद्योगों की जो क्षमता है,भविष्य में जो हमारे उद्योगों की क्षमता है,उनसे चर्चा करके यह तय किया जाता है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पिछले चार सालों में हमारा थाईलैंड से जो निर्यात है,यह 633 मिलियन डॉलर से लगभग 855 मिलियन डॉलर पहुंचा है। पिछले साल यह 855 मिलियन डॉलर था। माननीय सदस्य ने कहा कि इस समझौते के बाद कुछ लोगों को कठिनाई हुई है,यह बात सही है कि कुछ वस्तुएं चीन से भी आने लग गई,हमारा जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है,यह बात सही है,उसको बायपास करके। जैसा कि मैंने कहा कि इसका अनुभव हमको हो रहा है और इसमें हमारे जो भी उपाय हैं,प्रावधान हैं,उनका उपयोग करते हुए हमारी चर्चा चालू है। साथ ही मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत चिंता है कि हमारा जो मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर है,जिससे रोज़गार जुड़ा हुआ है,इसमें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है।

श्री जनार्दन द्विवेदी:सभापति महोदय,मंत्री जी के उत्तर का जो "क" भाग है, मुझे लगता है कि उसमें एक अंतर्विरोध है। मेरा प्रश्न यह है कि जहां उन्होंने पहले तो कहा है कि ऐसे हस्ताक्षर नहीं किए हैं,उसके बाद कहा कि मुख्य घटकों में वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में एफ.टी.ए. तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। ये अन्य क्षेत्र क्या हैं,जरा इसको बताएं।

दूसरा, प्रश्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:पहला ही काफी है,एक ही प्रश्न कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री जनार्दन द्विवेदी:यह इसी का हिस्सा है।

श्री सभापति:आपने खुद ही कहा कि दूसरा हिस्सा है।

श्री जनार्दन द्विवेदी:सर, इसी का दूसरा हिस्सा है,मैं अलग से प्रश्न नहीं कर रहा हूँ।

श्री सभापति:मैं दूसरे हिस्से को भी ऐलाऊ नहीं करुंगा, पहले हिस्से को ही ऐलाऊ करुंगा।

श्री कमल नाथ:सर,माननीय सदस्य का जो प्रश्न है,वह यह था कि आपने कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है,इस जवाब में मैंने कहा था कि भारत ने कोई पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया। साथ-साथ जवाब में मैंने यह भी कहा है, ताकि माननीय सदस्य को यह जानकारी मिल पाए कि जो ढांचा एग्रीमेंट हमने साइन किया है,जो कम्पोज़िट एग्रीमेंट हमने साइन किया है,उसका एक अंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और उसका एक अंग अर्ली हार्वेस्ट स्कीम है। उसके बाकी अंग जो हैं,वे हैं-

FTA in goods, services, investment in areas of economic cooperation.

MR. CHAIRMAN: Shri Alladi P. Rajkumar.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Thank you, Mr. Chairman. Sir, very recently, the Premier of China visited India. There was a talk going around regarding the Free Trade Agreement with China. What are the views of the Government in this regard? Are we going to lose in such an agreement since China has acquired the status of a manufacturing company for the world? Further, to enhance trade with China, what are the land routes that have been opened up or are proposed to be opened?

The third part of my question is that some time back there were talks about the Free Trade Agreement with Pakistan. What is the progress in that direction? (*Interruptions)....*

श्री सभापति:यह क्वेश्चन नहीं है। You limit yourself to Thailand… (Interruptions)…

डा.अलादी पी. राजकुमार:फ्री ट्रेड एग्रिमेंट पर मंत्री महोदय ने कहा है …(**व्यवधान**)…

MR. CHAIRMAN: If there is any question about the trade with Thailand, you put the question.

श्री कमल नाथ : सर, मैं इनको जानकारी दे दूं, जब चीन के प्रधानमंत्री आए थे, तो यह बात उठी थी । I am sorry. I will speak in English.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: No problem. He understands Hindi.

श्री कमल नाथ:सर,दिस मैटर हैड कम अप,यह बात चीन के प्रधानमंत्री के साथ हुई थी। आज प्रमुख बात यह है कि चाइना मार्किट इकोनोमी नहीं है। जब हम कोई भी व्यापार का समझौता करने जाते हैं, बहुत बडी आवश्यकता है और मै मानता हूँ कि आज इस पर,अगर हम ऐसा एग्रीमेंट करेंगे,जिस देश के साथ जो मार्किट इकोनोमी नहीं है,तो शायद हमारे देश के लिए लाभदायक न हो। कई प्रकार के निजी क्षेत्र में और निजी सोर्सेज से ये सुझाव आए कि हमें भी चीन के साथ ऐसा समझौता करना चाहिए। चीन विश्व के अन्य देशों के साथ …(**व्यवधान**)…

श्री सभापति:ठीक है,ठीक है।

श्री कमल नाथ:ऐसा समझौता कर रहा है,आसियन कंट्रीज के साथ। सर,जहां तक पाकिस्तान की बात है,पिछले नवम्बर माह में जब मैं पाकिस्तान में,इस्लामाबाद गया था,उस समय वहां के मंत्री ने और मैंने यह घोषणा की थी कि हम एक इकनोमी को-ऑपरेशन एग्रीमेंट के लिए स्टडी ग्रुप बना रहे हैं। जब यहां पर राष्ट्रपति मुशर्रफ जी आए थे तो इस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने भी यह इच्छा

जाहिर की थी कि हमारा व्यापार बढ़े। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:ठीक है,ठीक है। बहुत हो गया।

श्री कमल नाथ:आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि शक्कर की छूट पर ,जहां पहले ...(**व्यवधान**)... जो कुछ रोक या रुकावट थी ...(**व्यवधान**)... वह रोक रुकावट भी समाप्त हुई है।

श्री सभापति:आप बिल्कुल ...(**व्यवधान**)... बाहर चले गए हैं। श्री राजू परमार।

श्री राजू परमार:चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है,ऐसे ही क्या श्रीलंका के साथ भी पॉम ऑयल,सोयाबीन और वनस्पति घी के बारे में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है,यदि हुआ तो इसका क्या ब्यौरा है? क्या इस एग्रीमेंट की वजह से हमारी जो इंडियन कम्पनियां हैं, उनको कुछ नुकसान हो रहा है या नहीं?

श्री सभापति:आप क्वेश्चन के स्कोप से बाहर हैं। क्वेश्चन का स्कोप ही नहीं है।

श्री कमल नाथ:सर,भारत का ट्रेड एग्रीमेंट में पहला समझौता श्रीलंका के साथ लगभग चार साल पहले हुआ था। जैसा मैंने पहले उत्तर में कहा था कि इस प्रकार के समझौते में यह हमारा अनुभव था। यह बात सही है कि कई शिकायतें आईं कि चीन से डायवर्ट होकर श्रीलंका को बेस बनाकर,श्रीलंका को आधार बनाकर,यह बड़े सस्ते भाव में यहां आ रहा था। हमें कई चीजों के बारे में इस प्रकार की शिकायतें आईं,पेपर के बारे में, काली मिर्च के बारे में,वनस्पति के बारे में और तरह-तरह की चीजों के बारे में भी शिकायत आई है। इसलिए हमने श्रीलंका गवर्नमेंट से टेकअप किया है। गर्वनमेंट का ध्यान इस ओर पूरी तरह से आकर्षित है।

*142. [The questioner (Shri Shunmuga Sundram) was absent. For answer *vide* page 33]

Declaration of NIFT as deemed University

*143. SHRI LALITBHAI MEHTA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the National Institute of Fashion Technology awards any degree to those who complete four years' study successfully;

(b) to which university, the above Institute is affiliated;